



रेल दावा न्यायाधिकरण

जयपुर न्यायपीठ

RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

JAIPUR BENCH

दावा आवेदन संख्या - ओ.ए।।(यू)/जेपी/24/2020

दावा पंजीकरण तिथि : 06.02.2020

निर्णय तिथि : 14.08.2025

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व० नरेश शाह आयु लगभग 41 वर्ष।

निवासी पान- ग्राम व पोस्ट बाभन गांव, वार्ड संख्या 6, जिला खगडिया, बिहार
पिन 851204

.....प्रार्थिया/आवेदिका

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर।

.....प्रत्यर्थी/प्रतिप्रार्थी

उपस्थिति

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्रीमती नम्रता शर्मा।

प्रतिप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री खेम चन्द्र शर्मा।

निर्णय

1. प्रार्थिया ने अपने पुत्र की अनापेक्षित दुर्घटना में चलती ट्रेन से नीचे गिर जाने के कारण कुल 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) मय घटना की दिनांक 04.09.2019 से भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत ब्याज सहित रेल अधिनियम 1989 की धारा 125 संपटित धारा 16 रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 के अन्तर्गत, प्रतिकर की राशि प्राप्त करने के लिये दाखिल किया है।
2. दावा याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स. के साधारण डिब्बे

OAIIu/JP/24/2020



Scanned with OKEN Scanner



में कर रहा था। जब उक्त गाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन के पास किमी संख्या 920/12 के पास से गुजर रही थी, तो मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक गाड़ी में झटका लगने एवं अन्य यात्रियों के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाड़ी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में थानाधिकारी, जीआरपी, कोटा द्वारा एक मर्ग संख्या 54/2019 दर्ज की गई परन्तु मर्ग संख्या 54/2019 में घटना का विवरण किसी अन्य व्यक्ति का दर्ज किया गया है। उक्त मर्ग के अनुसार मृतक कि उम्र करीब 40-45 वर्ष अंकित की गई है जबकि मृतक कि उम्र करीब 23 वर्ष थी। उक्त मर्ग में घटना का विवरण गलत दर्ज किया गया है, घटना का सही विवरण थानाधिकारी, जीआरपी, कोटा द्वारा मेडीकल ज्यूरिस्ट, एमबीएस अस्पताल को लिखे पत्र में अंकित किया गया है जिसके अनुसार मृतक रविकेश उर्फ रिक्की पुत्र नरेश, उम्र 23 साल कोटा रेलवे स्टेशन की दक्षिण दिशा किमी नं. 920/12 पर किसी अज्ञात ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई है।

मृतक उक्त यात्रा अपने गांव जाने के लिए कर रहा था तथा मृतक आगे की यात्रा अन्य गाड़ी से करता परन्तु कोटा रेलवे स्टेशन के पास उक्त कारणवश सर्वोदय एक्स से गिरने से मृतक की मृत्यु हो गई। मृतक के पिताजी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है। मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की ने दिनांक 04.09.2019 को अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा के लिए एक द्वितीय श्रेणी का साधारण यात्रा टिकट खरीदा था। उक्त घटना में मृतक को गंभीर चोटें आईं जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई जिससे यात्रा टिकिट कहीं खो गया या गुम गया। मृतक का पर्स एवं एक बैग भी इस घटना कम में नहीं मिला, अगर यात्रा टिकिट पर्स या बैग के साथ चला गया हो तो या जीआरपी./आरपी.एफ./सिटी पुलिस की अभिरक्षा में हो तो उसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं है। मृतक उक्त दिवस उक्त यात्री गार्ड का वैध यात्री था।

प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मेडिकल ज्यूरिस्ट, को लिखा पत्र, मर्ग रिपोर्ट 54/2019, स्टेशन मास्टर कोटा द्वारा एसओ, जीआरपी को लिखा पत्र, नक्शा मौका घटनास्थल, फार्द सूरत हाल लाश, फार्द शिनाख्तगी लाश, फार्द सुपुर्दगी लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बयान अब्दुल करार, सुनीता देवी, रूपेश, बीरबल शाह, राजीव कुमार, दीपक, कुन्दन कुमार, मृतक का पहचान पत्र, प्रार्थिया का आधार



कार्ड, प्रमाणित प्रति, छायाप्रति बैंक पासबुक को दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया है।

प्रतिप्राथी ने अपना जवाबदाय मय मूल डीआरएम रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिप्राथी का कथन है दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्सप्रेस के साधारण डिब्बे में कर रहा था। जब उक्त गाड़ी रेलवे स्टेशन के पास कि.मी. 920/12 के पास से गुजर रही थी तो मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक गाड़ी में झटका लगने एवं अन्य यात्रियों के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाड़ी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई गलत व अस्वीकार है उक्त मद में वर्णित तथ्यों को प्राथीया रज्य सप्रमाण सावित करें। प्राथीया ने अपने क्लेम प्रार्थनापत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि अकरमात गाड़ी में झटका लगने एवं अन्य यात्रियों के दबाव व धक्का लगने से मृतक उक्त चलती गाड़ी में से नीचे गिर गया जबकि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में की गई जांच एवं गवाहों के कथनों से यह तथ्य सामने आये कि जीआरपी कोटा की पुलिस कार्यवाही में मृतक के पास से कोई रेल यात्रा टिकिट नहीं मिला है और ना ही प्राथीया ने अपने प्रार्थनापत्र में रेल यात्रा से सम्बन्धित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया है। पुलिस रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु रन ओवर का उल्लेख है तथा वर्णित गाड़ी के गार्ड श्री समित मजूमदार के बयान अनुसार गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान गाड़ी में किसी भी प्रकार का झटका या जर्क आदि नहीं लगना बताया गाड़ी में कोई एसीपी इत्यादि नहीं हुई और ना ही किसी यात्री के गिरने की सूचना गार्ड को किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई, उक्त घटना गार्ड की जानकारी में नहीं है पुलिस को मृतक की जामा तलाशी के दौरान कोई बैग व टिकिट नहीं मिला तथा मृतक रविकेश उर्फ रिक्की की मृत्यु गाड़ी नम्बर 12475 (सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस) से हुई इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहीं है। मृतक को रेल से यात्रा करते हुए एवं रेल से गिरने का कोई चश्मदीद गवाह सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट में सामने नहीं आया है मृतक की बाड़ी कोटा स्टेशन के होम सिग्नल के पास मिली थी जो कि एक व्यस्त रेल स्टेशन है और कोई व्यक्ति गाड़ी से गिरता तो अन्य राहयात्रियों के द्वारा रेलकर्मियों को अवश्य सूचना दी जाती उक्त दुर्घटना न तो किसी रेलकर्मियों के सज्जान में आई कि मृतक चलती गाड़ी से गिरा है ना ही किसी ने घटना होते देखी इससे स्पष्ट होता है कि मृतक की मृत्यु रेलवे गाड़ी से गिरकर नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी परिस्थिति से घटना घटित हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इर्रगुलर रेसिपरेशन से होना दर्शाया है।



पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेल से गिरकर मृत्यु होने का कथन नहीं किया है। अतः स्पष्ट साक्ष्य या चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में घटना धारा 123 (ग) रेल अधिनियम की श्रेणी में नहीं आती है इस कारण घटना के लिए विपक्षी अप्रार्थी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और ना ही प्रार्थीया क्लेम प्राप्त कर सकती है ऐसी स्थिति में क्लेम याचिका सरासर गलत होने के कारण खारिज किये जाने काबिल है।

प्रार्थीया द्वारा उक्त पैरा में यह जाहिर किया जाना कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थानाधिकारी जी.आर.पी. कोटा द्वारा एक नर्ग संख्या-54/2019 दर्ज की गई परन्तु नर्ग संख्या-54/2019 में घटना का विवरण किसी अन्य व्यक्ति का दर्ज किया गया है। उक्त नर्ग के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40-45 वर्ष अंकित की गई है जबकि मृतक की उम्र करीब 23 वर्ष थी। उक्त नर्ग में घटना का विवरण गलत दर्ज किया गया है, घटना का सही विवरण थानाधिकारी जी.आर.पी. कोटा द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट, एम.बी. एस. अस्पताल को लिखे पत्र में अंकित किया गया है जिसके अनुसार मृतक रविकेश उर्फ रिक्की पुत्र नरेश, उम्र 23 साल कोटा रेलवे स्टेशन की दक्षिण दिशा किमी नं. 920/12 पर किसी अज्ञात ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई है गलत व अस्वीकार है तथा उक्त पैराग्राफ में वर्णित तथ्य मिन विपक्षी से सम्बन्धित भी नहीं है इसलिए उक्त पैराग्राफ में वर्णित तथ्य को प्रार्थीया स्वयं अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनापत्र की मद संख्या-6 के उक्त पैराग्राफ में यह जाहिर किया जाना कि मृतक उक्त यात्रा अपने गांव जाने के लिए कर रहा था तथा मृतक आगे की यात्रा अन्य गाड़ी से करता परन्तु कोटा रेलवे स्टेशन के पास उक्त कारणवश सर्वोदय एक्सप्रेस से गिरने से मृतक की मृत्यु हो गई। मृतक के पिताजी का पूर्व में ही देहान्त हो चुका है उक्त पैराग्राफ में वर्णित में अस्वीकार है। प्रार्थीया ने अपने तथ्य जानकारी के अभाव प्रार्थनापत्र के उक्त पैराग्राफ में मृतक द्वारा आगे की यात्रा अन्य गाड़ी से करने का अभिकथन किया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीया ने स्पष्ट तौर से ना तो गाड़ी संख्या का और ना ही गाड़ी का नाम अंकित किया है इसलिए उक्त मद में वर्णित तथ्यों को प्रार्थीया स्वयं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करे।

प्रार्थनापत्र का मद नम्बर-7 में वर्णित जिस प्रकार से वर्णित किये गये हैं गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया के पुत्र रविकेश उर्फ रिक्की द्वारा उक्त मद में वर्णित टिकिट खरीद किया जाना तथा उस टिकिट से यात्रा किये जाने के तथ्यों



को प्रार्थीया स्वयं दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित करे। उक्त घटना की जाँच के दौरान मृतक के पास कोई भी यात्रा टिकिट अथवा अधिकार पत्र नहीं मिला और ना ही मृतक का ट्रेन में बैठकर यात्रा करने व ट्रेन से गिरने बावत कोई प्रत्यक्षदर्शी जाँच के दौरान नहीं आया है तथा प्रार्थीया द्वारा मृतक का पर्स व बेग घटना में नहीं मिलने की कोई भी शिकायत व एफ.आई.आर. कही दर्ज करवाई हो इसका कोई प्रमाण क्लेम के साथ पेश नहीं किया है किसी भी प्रकरण में प्रतिकर प्रदान करने के लिए वैध टिकिट सर्वप्रथम व आवश्यक शर्त होती है प्रार्थी ने अपने क्लेम प्रार्थनापत्र के साथ न तो कोई टिकिट पेश किया है और ना ही कोई साक्ष्य पेश की है जिसने मृतक को टिकिट खरीदते हुए देखा है उक्त समस्त तथ्य प्रार्थीया द्वारा मनगढ़न्त एवं बनावटी तथा क्लेम राशि प्राप्त करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है।

4. दावा आवेदन एवं जवाब दावा में उल्लेखित अभिवचनों के आधार पर, इस वाद में निम्नलिखित वाद विषय दिनांक 25.06.2021 को बनाए गये थे :

1. Whether the deceased was a bonafide passenger of the alleged train at the relevant time?
2. Whether the deceased died as a result of an untoward incident due to a fall from the passenger carrying train and whether the present case is covered under the definition of Section 123 (c) (2) of the Railway Act, 1989?
3. Whether the applicants are the sole dependents of the deceased and are entitled to compensation as claimed under Para-16 of the claim application?

5. Relief ?

5. दावा याचिका के समर्थन में प्रार्थीया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व० नरेश शाह ने अपना शपथ पत्र (एडव्ल्यू -1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थीया से दिनांक 05.09.2022 को प्रतिपरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया की ओर से इस दावे के समर्थन में, साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किये गये हैं।



क्र.स.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	प्रमाणित प्रति थानाधिकारी, जीआरपी, कोटा द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट एमबीएस अस्पताल, कोटा को लिखा पत्र	प्रदर्श-ए 1
2.	प्रमाणित प्रति मर्ग रिपोर्ट	प्रदर्श-ए 2
3.	प्रमाणित प्रति फर्द एस.एस. कोटा द्वारा जीआरपी कोटा को लिखा पत्र	प्रदर्श-ए 3
4.	प्रमाणित प्रति नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श-ए 4
5.	प्रमाणित प्रति फर्द सूस्त हाल लाश व पंचायतनामा	प्रदर्श-ए 5
6.	प्रमाणित प्रति फर्द शिनाख्तगी लाश	प्रदर्श-ए 6
7.	प्रमाणित प्रति फर्द सुपुदगी लाश	प्रदर्श-ए 7
8.	प्रमाणित प्रति पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श-ए 8
9.	प्रमाणित बयान अब्दुल करार, सुनीता देवी, रूपेश, वीरबल शाह, राजीव कुमार, दीपक, कुन्दन कुमार	प्रदर्श-ए 9 से 15
10.	प्रमाणित प्रति पहचान पत्र मृतक	प्रदर्श-ए 16
11.	प्रमाणित प्रति आधार कार्ड	प्रदर्श-ए 17
12.	प्रमाणित प्रति सरपंच, ग्राम कचहरी, द्वारा जारी पत्र	प्रदर्श-ए 18

6. श्री अशोक कुमार यादव पुत्र श्री भूप सिंह यादव, उप निरीक्षक, स्टेशन बारा कोटा मंडल, का शपथ पत्र (आर डब्ल्यू -1) मुख्य परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने श्री अशोक कुमार यादव, से दिनांक 13.10.2022 को प्रतिपरीक्षण किया गया एवं जवाब दावे के साथ प्रस्तुत की गई डी.आर.एम. रिपोर्ट प्रदर्श के रूप में अर्जित कर साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है।
7. अधिकरण के द्वारा पारित आदेश के तहत न्यायालयीन साक्षी उप निरीक्षक, जीआरपी, पुलिस, राजस्थान को समन जारी कर उसका परीक्षण दिनांक 22.04.2025 को न्यायालय द्वारा किया गया। प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण करने से इंकार किया गया।
8. प्रतिप्रार्थी ने डी.आर.एम. रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में कथित किया है। जीआरपी कोटा की पुलिस कार्यवाही में मृतक के पास से कोई वैद्य रेल यात्रा टिकिट नहीं मिला है, और ना ही वादी श्रीमति सुनीता देवी ने अपने वाद आवेदन में रेल यात्रा से सम्बंधित कोई भी वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वर्णित गाड़ी के गाई श्री

Sum



संगित मजूमदार के बयान अनुसार गार्ड ने अपनी ड्यूटी के दौरान गाड़ी में किसी भी प्रकार का झटका या जर्क आदि नहीं लगाया एवं गाड़ी में कोई एसीपी इत्यादि नहीं होना और ना ही किसी यात्री के गिरने की सूचना गार्ड को किसी के द्वारा नहीं दी गई. उक्त घटना गार्ड की जानकारी में नहीं है। गार्ड द्वारा वर्णित गाड़ी का बार्ज गार्ड श्री वीरेंद्र सिंह चंदेल मुख्यालय कोटा को खेरियत से दिया। उक्त घटना के संवध में डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ईरैगुलर रेस्पिरेशन, हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी के कारण मृत्यु होना दर्शाया है। मृतक रविकेश उर्फ रिक्की की मृत्यु गाड़ी नं० 12475 (सर्वोदय सुपरफास्ट एक्सप्रेस) से हुई है इसका कोई प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहीं है। मृतक ने घटना को मृत्युदायक नहीं समझा अपने जीवन को खतरे में डालकर लापरवाही पूर्वक उक्त घटना कारित हुई है। अतः स्पष्ट साक्ष्य या वध्मदीद गवाह की अनुपस्थिति में घटना धारा-123 (ग) रेल अधिनियम की श्रेणी में नहीं आती है।

9. प्रार्थी व प्रतिप्रार्थी अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया, वाद विषय की विवेचना इस प्रकार है :

निर्णय के कारण

Decision with Reason

वाद विषय : 01 व 02

सुविधा के दृष्टिकोण से एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो जिस कारण से वाद विषय क्रमांक 1 व 2 पर एक साथ विचारण किया जा रहा है।

10. दावा याचिका के अभिवचनों को प्रमाणित करने बाबत प्रार्थिया सुनीता देवी ने स्वयं का शपथ पत्र एडव्ल्यू-1 के रूप में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने दावा याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये कथित घटना उल्लेखित कर कथित किया की उसका पुत्र दिनांक 04.09.2019 को अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्सप्रेस में कर रहा था व जब उक्त गाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन कि. मी. नम्बर 920/12 के पास से गुजर रही थी तब मृतक पेशाब कर अपनी सीट पर वापस जाते समय गाड़ी से नीचे गिर गया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरिक्षण के दौरान साक्षी ने कथित किया है कि घटना की जानकारी मुझे मोबाइल द्वारा पुलिस ने दी थी, मैं मोर्के पर नहीं गई थी व मेरे पुत्र के पास टिकिट था। इस साक्षी ने प्रतिप्रार्थी के इस तथ्य को प्रतिपरिक्षण में गलत कहा है



कि उक्त घटना मेरे घटे की ट्रेन से रनओवर होने के कारण घटित हुई है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि जिससे इस साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जा सके।

मृतक ग्राम बागन गांव, वार्ड सं-6, जिला- खगड़िया, (बिहार) का निवासी होना पाया गया है एवं घटना के समय अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा करना दर्शाया गया है एवं उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे कोटा रेलवे स्टेशन के पूर्व पाया गया है। उक्त स्थान एक ऐसा स्थान है जहां मृतक के स्वयं किसी साधन से पहुँचने की संभावना ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में इस बात की एक स्पष्ट धारणा की जा सकती है कि मृतक अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन के पूर्व चलती ट्रेन से गिरा था।

घटना के संबंध में दिनांक 04.09.2019 को 23:15 बजे स्टेशन अधीक्षक, कोटा के द्वारा जीआरपी, कोटा को मेमो प्रदर्श- ए 3 जारी किया है जिसमें उचित किया गया है कि डाउन मालगाड़ी के एल.पी. ने वीएचएफ सेट पर सूचना दी है कि कि.मी. 920/12 डाउन लाईन के पास डैडवॉडी पड़ी है उचित कार्यवाही करे। नक्शा मौका प्रदर्श- ए 4 में मृतक का शव डाउन लाईन के किनारे दर्शाया गया है। जीआरपी द्वारा अन्वेषण के दौरान लाश पंचायतनामा प्रदर्श- ए 5 तैयार किया गया जिसमें पंचों के द्वारा मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने व शरीर पर आई चोटों के कारण दर्शाया गया है व मृतक के शरीर में उसकी दाढ़ी के नीचे गहरी चोट व जगह-जगह रगड़ व कालिख के निशान होना लाश पंचायतनामा में उल्लेखित किया गया है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श- ए 8 में भी शरीर पर फटे हुये घाव एवं खरोंच के निशान होना दर्शित कर मृतक की मृत्यु का कारण अनियमित श्वसन जोकि सिर की चोट व छाती की चोट से होना दर्शित किया गया है। स्टेशन मास्टर के मेमो के अनुसार मृतक का शव 23:15 बजे सूचना प्राप्त हो के बाद जारी किया जाना दर्शित है एवं सर्वोदय एक्सप्रेस कोटा स्टेशन पर 22:20 बजे आकर 22:30 बजे प्रस्थान किया जाना डीआरएग रिपोर्ट के साथ सलग्न चार्ट में दर्शित है जिससे स्पष्ट होता है कि मृतक का शव उक्त ट्रेन के जाने के पश्चात ही पाया गया है। अतएव उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से भी मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने से आई चोटों से होना स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है।

प्रतिप्रार्थी के साक्षी अशोक यादव, उपनिरीक्षक, रेलवे स्टेशन बारा, मंडल कोटा की साक्ष्य से घटना के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं मिलती है इस साक्षी के



द्वारा मात्र समाधान के आधार पर मृतक का रनओवर होना कथित किया है। न्यायालयीय साक्षी सीडब्ल्यू-1 अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथित किया है कि उसे जाँच के दौरान उसे कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं मिला परंतु उसके द्वारा पचों के एवं मृतक की माँ श्रीमती सुनीता देवी के बयान लिये गये। इस साक्षी ने यह भी कथित किया है कि उसने अंतिम जाँच प्रतिवेदन में लेख किया है कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने से शरीर पर आई चोट के कारण हुई है।

प्रतिप्राथी के अधिवक्ता के द्वारा भी बहस के दौरान कथित किया है कि घटना के संबंध में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जिस कारण से अनापेक्षित घटना सिद्ध नहीं होती है। प्रतिप्राथी का उक्त कथन मान्य किये जाने के योग्य नहीं है कि क्योंकि प्राथिया के साक्षी के द्वारा शपथ पत्रिय साक्ष्य में घटना को सिद्ध किया गया है एवं घटना पुलिस के द्वारा अन्वेषण के द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजों से भी सिद्ध होती है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने *Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar*, (2008) 9 SCC 527 में निर्धारित किया है कि :-

Since the provision for compensation in the Railways Act is a beneficial piece of legislation, in our opinion, it should receive a liberal and wider interpretation and not a narrow and technical one. Hence, in our opinion the latter of the abovementioned two interpretations i.e. the one which advances the object of the statute and serves its purpose should be preferred

It is well settled that if the words used in a beneficial or welfare statute are capable of two constructions, the one which is more in consonance with the object of the Act and for the benefit of the person for whom the Act was made should be preferred. In other words, beneficial or welfare statutes should be given a liberal and not literal or strict interpretation

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर रेलवे अधिनियम एक लाभकारी विधान है एवं लाभकारी विधान में प्रयुक्त शब्दों के यदि दो अर्थ निकलते हैं तो ऐसे अर्थ को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जिसके उद्देश्य



हेतु उक्त विधान को निर्मित किया एवं लाभकारी विधान की ऐसी उदार व्याख्या की जानी चाहिये जिससे उसे निर्मित किये जाने का उद्देश्य सफल हो सके।

प्रतिप्राथी के अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथित किया है कि आरोपित घटना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा (क) के उपखण्ड (ख) एवं (ग) की श्रेणी की होने से अनापेक्षित घटना की श्रेणी में नहीं आती है, जिस कारण से रेलवे प्रशासन क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु उत्तरदायी नहीं है। प्रतिप्राथी अधिवक्ता का यह कथन मान्य किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के मामले में निर्धारित किया है कि

".....Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 124 (क) के अपवाद (ख) "स्वयं को पहुंचाई गई क्षति" के संबंध में निर्धारित किया है कि :-

".....the concept of "self-inflicted injury" would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree. Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on "no fault theory". We may in this connection refer to the judgment of this Court in *United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar* [*United India Insurance Co. Ltd. v. Sunil Kumar*, (2019) 12 SCC 398; 2017 SCC OnLine SC 1443; (2017) 13 Scale 652] laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on "no fault theory" under Section 163-A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an "untoward incident" entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124-A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त मामले में यह भी निर्धारित किया है कि :-

".....In *Prabhakaran Vijaya Kumar* (supra) it was held that Section 124A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required."

Law



उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टान से स्पष्ट है कि "स्वयं को पहुंचाई गई क्षति" व "स्वयं का अपराधिक कृत्य" को प्रमाणित किये जाने वायत मृतक का आशय अथवा अपराधिक दुराशय प्रमाणित किया जाना आवश्यक है परंतु प्रतिप्रार्थी के द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घटना में मृतक का स्वयं को क्षति पहुंचाने का कोई आशय अथवा अपराधिक दुराशय रहा है एवं घटना धारा 124 (क) के अपवाद (ख) व (ग) में आती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने (2019) 3 Supreme Court Cases 572 Union of India Vs Rina Devi के प्रकरण में निर्धारित किया है कि :-

Mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found.

प्रार्थिया के द्वारा अपने शपथ पत्र में मृतक के द्वारा द्वितीय श्रेणी का साधारण टिकिट कय कर यात्रा करना एवं घटना के दौरान यात्रा टिकिट गुम हो जाना व्यक्त किया है एवं यह भी कथित किया है कि मृतक का पर्स एवं बैग भी घटना क्म में नहीं मिला एवं मृतक घटना दिनांक को यात्री गाडी में एक वैध यात्री था। अनापेक्षित घटना में जहां पर मृतक के शरीर पर चोटें आई हैं एवं उसे घटनास्थल से पुलिस के द्वारा उठाकर ले जाया गया व अस्पताल में उसका शय परिक्षण किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में टिकिट गुम हो जाने की समावना से इकार नहीं किया जा सकता। माननीय सच्चैतम न्यायालय ने भी उपरोक्त प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि मात्र टिकिट ना मिलने से यह नहीं माना जा सकता है कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री नहीं था। रेलवे प्रशासन द्वारा भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिससे यह सिद्ध हो की मृतक घटना के समय बिना यात्रा टिकिट के यात्रा कर रहा था। अतएव मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था।

Four



उपरोक्त वर्णित मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत के आधार पर मैं यह निर्धारित करता हूँ कि दिनांक 04.09.2019 को मृतक रविकेश कुमार उर्फ रिक्की अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स के साधारण डिब्बे में कर रहा था, जब उक्त गाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन के पास कि.मी. संख्या 920/12 के पास से गुजर रही थी, तो मृतक उक्त चलती गाड़ी से नीचे गिर गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अतएव मृतक घटना के समय धारा 2 (29) रेलवे अधिनियम में परिभाषित अनुराग सदभावी यात्री था व कथित घटना धारा 123 (सी) (2) व 124 ए रेलवे अधिनियम के तहत अनापेक्षित घटना की श्रेणी में आती है, जो उक्त धारा उल्लेखित अपवादों की श्रेणी की नहीं है। अतएव वाद विषय क्रमांक 1 व 2 प्रार्थिया के पक्ष व प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये जाते हैं।

विवादक संख्या: 03

11. प्रार्थिया मृतक की माता है उक्त आशय के कथन प्रार्थिया ने अपने शपथ पत्र में कथित किये हैं एवं उसने यह भी कथित किया है कि वह मृतक पर पूर्णता आश्रित थी उसके पति का स्वर्गवास हो चुका है व उसका पुत्र रविकेश अविवाहीत था। प्रतिप्रार्थी के द्वारा उपरोक्त तथ्यों के संबंध में कोई विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं दावा याचिका के लम्बन रहने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा स्वयं को मृतक का आश्रित होना नहीं बताया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया के द्वारा स्वयं के आधार कार्ड प्रदर्श ए 7 एवं सरपंच ग्राम कचहरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि मृतक प्रार्थिया का पुत्र था। प्रार्थिया धारा 123 बी रेलवे अधिनियम के तहत आश्रित की श्रेणी में आती है। अतएव वाद विषय क्रमांक 3 उपरोक्तानुसार निर्णित किया जाता है।

विवादक संख्या: 04

12. मृतक श्री रविकेश घटना दिनांक 04.09.2019 को सदभावी यात्री के नाते अहमदाबाद से मथुरा की यात्रा सर्वोदय एक्स के साधारण डिब्बे से यात्रा के दौरान अनापेक्षित घटना में ट्रेन से गिर कर मृत हुआ जिस कारण से मृतक की एक मात्र आश्रित उसकी माता प्रार्थिया रेलवे प्रशासन से मुआवजा राशि रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) रेलवे दुर्घटना व अनापेक्षित घटना नियम 1990 के नियम 3(3) की अनुसूची के पार्ट एक में उल्लेखित अनुसार प्राप्त करने की अधिकारी



है। प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब प्रार्थिया की ओर से कारित किया गया है जिस कारण से घटना दिनांक से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित नहीं है। अतएव प्रार्थिया उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि रुपये 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) पर दावा पुनर्स्थापित दिनांक 28.02.2024 से अधिकरण के अपर निवधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार वाद विषय क्रमांक 04 निर्णित किया जाता है।

आदेश ORDER

13. यह दावा प्रार्थिया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। प्रार्थिया को रु 8,00,000/- (रु आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया को दावा पुनर्स्थापित दिनांक 28.02.2024 से मुआवजा राशि के अधिकरण के अपर निवधक के Suitor Money Account में जमा करने की दिनांक तक मुआवजा राशि पर 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है।

प्रार्थिया का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का वितरण	
		मजद राशि	एन्क्यूटी/ संचालि राशि
श्रीमती सुनीता देवी पानी रूथ श्री नरेश शाह	रु 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र)	रु 80,000/- (रुपये अरसी हजार मात्र) सम्पूर्ण ब्याज राशि	रु 7,20,000/- (सात लाख बीस हजार रुपये मात्र) इस राशि को तीन वर्ष की अवधि हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि में जमा रखा जायेगा। इस सावधि पर मिलने वाले मासिक ब्याज की राशि प्रार्थिया को उसके बचत खाते में भुगतान करके अदा कि जायेगी।

14. प्रतिप्रार्थी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निवधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, जयपुर के स्कुटर मनी (Suitor Money) एकाउंट में इस आदेश की दिनांक से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिप्रार्थी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यूटीआर नंबर, ब्याज की गणना सहित

Sum



आवेदक की मुआवजा राशि इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदक को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर नियमक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ एओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया -

5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untowards Incidents (Compensation) Rules, 1990

1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the award. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk fund in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No. 31521-31522 OF 2017. A Statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant...."

16. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किये गये आदेश के अनुपालना में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुये रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है:-

"5. Mode of Payment-



- 5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimants, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable means as shall subserve justice.
- 5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.
- 5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursement for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.
- 5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.
17. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अग्निकृत दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण धरण क्रमांक 13 में उल्लेखित अनुसार किया जावे।
18. प्रार्थिया को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के व्यक्तिगत बचत खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।
19. यदि प्रार्थिया टीडीएस कटौती की छूट का हकदार है तो वह फार्म-15जी या फार्म-15-एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष जमा करे एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जायेगी।

20 जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाये:-



1. प्रार्थिया के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते अनुमति नहीं देगा।
 2. इस अधिकरण की अनुमति के बिना प्रार्थिया की सावधि जमा कर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।
 3. बैंक प्रार्थिया को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।
 4. बैंक प्रार्थिया की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि प्रार्थिया को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किये गये हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किये जायेगा। प्रार्थिया उक्त प्रविष्टि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
21. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 14.08.2025 को अधिघोषित किया गया।

(राजीव जैन)

सदस्य (न्यायिक)

रेल दावा अधिकरण/जयपुर पीठ